<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052024-254378 CG-DL-E-27052024-254378

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139] No. 139] नई दिल्ली, सोमवार, मई 27, 2024/ज्येष्ठ 6, 1946 NEW DELHI, MONDAY, MAY 27, 2024/JYAISTHA 6, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय (केंद्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड)

संकल्प

नई दिल्ली, 27 मई, 2024

संख्या यू-23013/02/2018-एलडब्ल्यू(बी).—ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड एतद्वारा नौकरी में अर्थात पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के प्रतिष्ठान में अवर श्रेणी लिपिक, लिफ्ट ऑपरेटर, डीईओ, सेनेटरी इंस्पेक्टर, एमआरआई, स्टेनोग्राफर, स्टोरकीपर, रिसेप्शनिस्ट, ड्राइवर, टेलीफोन ऑपरेटर, डीआरओए, कलाकार सह कंप्यूटर ग्राफिस्ट, कनिष्ठ अभियंता (टेलीफोन), प्रयोगशाला परिचारक, डार्क रूम सहायक आदि में ठेका श्रम के उन्मूलन संबंधी प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन करता है। समिति की संरचना और विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे: -

1. श्री जयंत एस. देशपांडे

सदस्य

ई-88, अमर कॉलोनी, रघुनाथ मंदिर के पास, लाजपत नगर-4, नई दिल्ली -110024.

2. श्री कुणाल रावत,

सदस्य

राष्ट्रीय सचिव,

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और

राजस्थान राज्य की अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन

3220 GI/2024

कांग्रेस समिति के महासचिव,

35-36, रंजीत नगर, खातीपुरा, जयपुर-302012.

3. श्री बी.के. भाटिया,

सदस्य

अपर महासचिव.

भारतीय खनिज उद्योग संघ (एफआईएमआई),

एफआईएमआई हाउस, बी-311, ओखला औद्योगिक क्षेत्र,

फेज-I, नई दिल्ली-110020.

4. उप केंद्रीय श्रम आयुक्त (कें.) (सी), चंडीगढ़

सदस्य-संयोजक

प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:-

- (1) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के प्रतिष्ठान में नौकरी/कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली के कामकाज का अध्ययन करना और उसमें से ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त करने की मांग पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय में 2022 की सिविल रिट याचिका 4291 में की गई है।
- (2) समिति को उपयुक्त सिफारिश करनी है कि क्या ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा (10) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के प्रतिष्ठान में ऊपर उल्लिखित नौकरी/कार्यों में ठेका कामगारों के रोजगार का उन्मूलन किया जाए या नहीं।
- (3) सिमिति की रिपोर्ट 01 महीने के भीतर हर हाल में प्रस्तुत की जानी है। चूंकि मामला न्यायालय की अवमानना से संबंधित है और बोर्ड, चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यथानिर्देशित निर्धारित समय के अंतर्गत इस पर निर्णय लेने के लिए बाध्य है।
- (4) समिति का मुख्यालय चंडीगढ़ में होगा।

कमल किशोर सोन, अपर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(Central Advisory Contract Labour Board)

RESOULATION

New Delhi, the 27th May, 2024

No. U-23013/02/2018-LW(B).—In exercise of the Power Conferred by Section- 5 of the Contract Labour (R&A) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby Constitutes a Committee to go into the question of abolition of Contract Labour in the Job i.e. LDC, Lift operator, DEO, Sanitary Inspector, MRI, Stenographer, Storekeeper, Receptionist, Driver, Telephone operator, DROA, Artist cum Computer Graphist, Junior Engineer (Telephone). Laboratory attendant, Dark Room Asstt. Etc in the establishment of PGIMER, Chandigarh. The composition of Committee and term of reference will be as under:-

1. Shri Jayant S. Deshpande,

Member

E-88, Amar Colony, Near Raghunath Mandir,

Lajpat Nagar-4, New Delhi-110024

2. Sh. Kunal Rawat,

Member

National Secretary,

All India Trade Union Congress and

General Secretary Rajasthan State Committee of

All India Trade Union Congress,

35-36, Ranjeet Nagar, Khatipura, Jaipur-302012.

3. Shri B.K. Bhatia,

Member

Additional Secretary General,

Federation of Indian Mineral Industries (FIMI),

FIMI House, B-311, Okhla Industrial Area,

Phase-I, New Delhi-110020.

4. Dy. CLC(C), Chandigarh.

Member-Convener

The term of reference of Proposed Committee would be as follows:-

- (1) To study the working of Contract Labour system in the Job/Works in the Establishment of PGIMER, Chandigarh as mentioned above and of which abolition of Contract Labour System has been Sought in Civil Writ Petition 4291 of 2022 in the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana at Chandigarh.
- (2) The Committee has to make suitable recommendation whether or not employment of Contract Labour in Job/Works as mentioned above in the establishment of PGIMER, Chandigarh be prohibited keeping in view the provisions of Section (10) of Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970.
- (3) The report of Committee must be Submitted within 01 month positively as the case is related to contempt and board is duly bound to decide it within the stipulate time as directed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana at Chandigarh.
- (4) The Head Quarter of Committee will be at Chandigarh.

KAMAL KISHORE SOAN, Addl. Secy.